प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
27.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। शिमला में आज विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक संस्थान में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 4 से 6 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मज़बूत करने पर बल देते हुए कहा कि ओरल हैल्थ स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हज़ारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें विशेषज्ञ व रेज़िडेंट डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरा–मैडिकल स्टाफ शामिल है। धनीराम शांडिल ने अधिकारियों को प्रदेशभर में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए।

विधानसभा सत्र

प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला स्थित तपोवन में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि इस सत्र में कुल 4 बैठकें आयोजित की जाएँगी और यह वर्तमान सरकार का सातवां सत्र होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि तपोवन में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियों के लिए ज़िला प्रशासन को दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार का दो साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। शिमला में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल फॉर सेल शुरू कर दिया है और पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचने की साजिश रची जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है, इसके बावजूद सरकार जश्न मनाने की बात कर रही

है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 20 साल पीछे धकेल दिया है और सुक्खू सरकार प्रदेश की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने आज शिमला स्थित राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुल बजट का 20 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, ताकि हर बच्चे को बेहतर व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्कूल के सभी शिक्षकों से दिसंबर में आयोजित किए जा रहे परख कार्यक्रम के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर काम करने वाले शिक्षकों और मेधावी विद्यार्थियों को एक्सपोज़र टूर भी करवाए जा रहे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल की प्रतिभावान व मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया और स्कूल द्वारा प्रकाशित सामरिक वाटिका 2024–25 का विमोचन भी किया।

प्रतिभा सिंह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश के सभी ज़िलों के चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के कर्मठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान देने पर बल दिया। प्रतिभा सिंह ने ज़िला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के गठन को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित युवाओं, अग्रणी संगठनों के कार्यकर्ताओं और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश मामलों के सह–प्रभारी चेतन चौहान ने सभी ज़िला पर्यवेक्षकों से अपना दायित्व सही ढंग से पूरा करने व इसकी रिपोर्ट जल्द देने का आह्वान किया। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दूध व सब्जियों की ढुलाई निःशुल्क किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है।

अन्न योजना

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन बंभानिया ने बताया कि अगले पांच वर्षों के लिए योजना को

जारी रखने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि जनवरी, 2024 से आगे पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है।